



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, मंगलवार 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जनवरी, 2012

**संख्या इण्ड-II (एफ) 6-5/2006.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरल्ज (कन्सेशन) रिवाइज्ड रूलज, 1971 के रूल 20 के सब-रूल (2) के अधीन उन्हें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों से संलग्न फर्स्ट शैड्यूल में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:—

**फर्स्ट शैड्यूल का प्रतिस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरल्ज (कन्सेशन) रिवाइज्ड रूलज, 1971 से संलग्न फर्स्ट शैड्यूल के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

Sr. No.	Name of Mineral (per tonne)	Rate of Royalty
1.	Building stones, Masonry stones including Boulders and Shingle.	Rs. 40.00
2.	Limestone	Rs. 65.00
3.	Marble:	
	(a) Used for lime burning	Rs. 65.00
	(b) Dressed, carved and rough marble slabs.	Rs. 300.00
	(c) Marble chips, fine powder, Khandas.	Rs. 65.00
	(d) Coarse powder of not more than plus 20 mash.	Rs. 65.00
4.	Bajri	Rs. 40.00
5.	Brick earth	Rs. 20.00
6.	Ordinary sand/clay/shale	Rs. 40.00
7.	(a) Rough slab slate	Rs. 100.00
	(b) Slate Rs. 300.00	
	(c) Quartzite slate	Rs. 300.00
8.	Kankar, road metal, blast and rorri.	Rs. 40.00
9.	Cut or dressed blocks of granite and traps/basalt including rocks of other colours and shades (size 180x80x50 cms or more).	Rs. 400.00
10.	All other minor mineral not herein specified.	25% of the Sale value at pit mouth."

यह संशोधन इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
प्रधान सचिव (उद्योग)।

*[Authoritative English text of this department notification number Ind-II(F)6-5/2006 dated 16.1.2012 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India].*

## INDUSTRIES DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 16<sup>th</sup> January, 2012*

**No.Ind-II(F)6-5/2006.**—In exercise of the power vested in her under sub-rule (2) of rule 20 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) Revised Rules, 1971, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in the First Schedule appended to the said Rules, namely:-

**Substitution of First Schedule.**—For the First Schedule appended to the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) Revised Rules, 1971, the following shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Name of Mineral (per tonne)	Rate of Royalty
1.	Building stones, Masonry stones including Boulders and Shingle.	Rs. 40.00
2.	Limestone	Rs. 65.00
3.	Marble:	
	(a) Used for lime burning	Rs. 65.00
	(b) Dressed, carved and rough marble slabs.	Rs. 300.00
	(c) Marble chips, fine powder, Khandas.	Rs. 65.00
	(d) Coarse powder of not more than plus 20 mash.	Rs. 65.00
4.	Bajri	Rs. 40.00
5.	Brick earth	Rs. 20.00
6.	Ordinary sand/clay/shale	Rs. 40.00
7.	(a) Rough slab slate	Rs. 100.00
	(b) Slate	Rs. 300.00
	(c) Quartzite slate	Rs. 300.00
8.	Kankar, road metal, blast and Rorri.	Rs. 40.00
9.	Cut or dressed blocks of granite and traps/basalt including rocks of other colours and shades (size 180x80x50 cms or more).	Rs. 400.00
10.	All other minor minerals not herein specified.	25% of the Sale value at pit mouth."

This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,  
Sd/-  
Principal Secretary (Industries).

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 2012

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी) एफ (5)87/2011.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव पान्दली, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि

अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र ( हैक्टेयर में)
शिमला	कोटखाई	पान्दली	800 / 1	0-03-46
			807 / 1	0-00-11
			कुल जोड़ किता-2	0-03-57

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 2012

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू.(बी) एफ (5)86/2011.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव अणू, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द० क्षे०), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र ( हैक्टेयर में)
शिमला	कोटखाई	अणू	148 / 2	0-09-57
			153	0-09-62
			कुल जोड़ किता-2	0-19-19

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 2012

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी) एफ (5)84/2011.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव जलटाहर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द० क्षे०), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र ( हैक्टेयर में)
शिमला	कोटखाई	जलटाहर	136	0-01-76
			152 / 1	0-00-44
			कुल जोड़ किता-2	0-02-20

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 2012

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी) एफ (5)81/2011.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव धार, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में टियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द० क्षे०), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

## विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र ( हैक्टेयर में)
शिमला	कोटखाई	धार	967	0-23-02
			30	0-04-23
			955	0-04-72
			961	0-08-34
			28	0-00-42
			25	0-00-86
			कुल जोड़ किता-6	0-41-59

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 13 जनवरी, 2012

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी) एफ (5)80/2011.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव बराडा, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में टियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द० क्षे०), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

#### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र ( हैक्टेयर में)
शिमला	रोहडू	बराडा	1344	0-02-94
कुल जोड़ किता-21				0-02-94

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

#### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 2012

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू.(बी) एफ (5)78/2011.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कसौली, तहसील कसौली, जिला सोलन, में गढखल-गुनाई सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि० क्षे०), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

#### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा)
सोलन	कसौली	कसौली	492	0-7
			497	0-4
कुल जोड़ किता-2				0-11

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 2012

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी) एफ (5)79/2011.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव दोहची, तहसील कसौली, जिला सोलन, में किम्पूघाट-चक्की का मोड सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

## विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा)
सोलन	कसौली	दोहची	198/78/2/2/1	1-0
कुल जोड़ किता-1				1-0

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 12 जनवरी, 2012

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी) एफ (5)176/2008.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव हार, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, में भवारना-जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश



करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

#### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
कांगड़ा	पालमपुर	हार	274 / 2 / 1	0-00-48
			275 / 2 / 1	0-00-80
			कुल जोड़ किता-2	0-01-28

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

#### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 2012

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी) एफ (5)175/2009.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव/मौजा भवारना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, में भवारना-जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

#### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
कांगड़ा	पालमपुर	भवारना	1388 / 1	0-00-26
			1389 / 1	0-01-00
			1390 / 1	0-00-25
			1391	0-00-74
			कुल जोड़ किता-4	0-02-25

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 13 जनवरी, 2012

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी) एफ (5)177/2009.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव चंजहेड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, में भवारना-जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

## विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
कांगड़ा	पालमपुर	चंजहेड	585/417/1	0-01-15
			586/417/1	0-02-07
			कुल जोड़ किता-2	0-03-22

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 13 जनवरी, 2012

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी) एफ (5)163/2009.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव थली, तहसील करसोग, जिला मण्डी, में जीप योग्य पुल के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा-विस्वा में)
मण्डी	करसोग	थली	77	0-01-08
			120	0-06-00
			121	0-06-09
			1413 / 122	0-08-16
			1414 / 122	0-08-16
			कुल जोड़ किता-5	0-11-09

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / -  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 04th June, 2011*

**No. 11-2/95(lab) ID/Kinnour.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Ashok Kumar Thakur C/O CITU Office, Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. V/s The General Manager, M/S SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project, Kinnour, Distt. Kinnour, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether termination of the services of Sh. Ashok Kumar Thakur (Electrician) C/O CITU Office Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. by the management of M/s SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project. Kinnour, Distt.

Kinnour, H.P. w.e.f. 13.4.2010 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the above named workman is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the concerned management?"

Sd/-  
Labour Commissioner.

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 04th June, 2011*

**No. 11-2/95(lab) ID/Kinnour.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Ashwani C/O CITU Office, Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. V/s The General manager, M/S SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project, Kinnour, Distt. Kinnour, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether termination of the services of Sh. Ashwani (Welder) C/O CITU Office Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. by the management of M/s SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project. Kinnour, Distt. Kinnour, H.P. w.e.f. 13.4.2010 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the above named workman is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the concerned management?”

Sd/-  
Labour Commissioner.

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 02nd June, 2011*

**No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Mandi.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Smt. Kalan Devi W/O Sh. Beli Ram, Village-Bhawana, PO Jarol, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi, H.P. V/s The Divisional Forest Officer, Suket Forest Division Sunder Nagar, Distt. Mandi, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether verbal termination of the services of Smt. Kalan Devi W/O Sh. Beli Ram, daily wage workman by the The Divisional Forest Officer, Suket Forest Division Sundar Nagar, Distt. Mandi w.e.f. 06.9.2009 without serving notice, without holding enquiry and without following the provision of the Industrial disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the concerned employer?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 25th June, 2011*

**No. 11-6/85(Lab) ID/11/Shimla.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Manish Kr. Prasad R/O Verma Niwas, Flat No.-2, Opposite Block No. 27, Sector-III, New Shimla, H.P. Vs. i) Head (HR), Development Alternative Group, B-32, Tara Crescent Qutab, Institutional Area, New Delhi 110016. ii) The Vice President/Manager, Development Alternative Group, Set No. 4, Block 6, Phase III, New Shimla, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

*“Whether Sh. Manish Kr. Prasad, Programme Executive, is a workman as per provisions of section 2 (s) of The Industrial Disputes Act, 1947?”*

*“If yes, “Whether termination of the services of Sh. Manish Kr. Prasad w.e.f. 30.11.2009, who was employed on contract as Programme Executive, for a period of one year, by the Head (HR), Development Alternative Group, B-32, Tara Crescent Qutab, Institutional Area, New Delhi 110016 ii) The Vice President/Manager, Development Alternative Group, Set No. 4, Block 6, Phase III, New Shimla, H.P., after completion of 3 month service, without serving notice, withoutholding enquiry and without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits & relief Sh. Manish Kr. Prasad is entitled to from the concerned management?”*

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 22nd June, 2011*

**No. 11-2/86(Lab) ID/2011/Bilaspur.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Miss Neena Kumari D/O Sh. Sita Ram, R/O Village-Badyat, P.O. & Tehsil Sadar, Dist. Bilaspur, H.P. V/s i) The Regional Project Director, Mid Himalyan Watershed Development Project, Lakhanpur, Distt. Bilaspur, H.P. ii) The Divisional Watershed Development Officer, Bahadurpur Watershed Division at Namhol, Distt. Bilaspur, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

*“Whether verbal termination of the service of Miss Neena Kumari D/O Sh. Sita Ram, Daily Wage Data Entry Operator/Social Mobilizer by the The Divisional Watershed Development Officer, Bahadurpur Watershed Division at Namhol, Distt. Bilaspur, (H.P.) w.e.f. 06.2.2010 without following the provision of the Industrial Disputes Act, 1947 and retaining junior workmen as alleged by worker, is legal nad justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the concerned employer?”*

Sd/-

*Labour Commissioner.*

**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, the 22nd June, 2011*

**No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Mandi.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Prem Singh S/O Sh. Achhar Singh, Village Sundal, P.O. Tor Jajar (Mandap), Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/s The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“ Whether plea of the employer i.e. Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi that services of the Sh. Prem Singh S/O Sh. Achhar Singh has not been terminated but he has abandoned the services w.e.f. 29.5.2006 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

---

**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, the 2nd June, 2011*

**No. 11-2/95(lab) ID/Kinnour.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Sami Ram C/O CITU Office, Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. V/s The General manager, M/S SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project, Kinnour, Distt. Kinnour, H. P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)

this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether termination of the services of Sh. Sami Ram (Welder) C/O CITU Office Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. by the management of M/s SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project. Kinnour, Distt. Kinnour, H.P. w.e.f. 13.4.2010 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the above named workman is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the concerned management?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 27th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Chaman Lal S/O Shri Prithi Chand R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Chaman Lal S/O Shri Prithi Chand Senior Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*



**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, the 8th June, 2011*

**No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Chhering Butit W/O Shri Chhering Chhutup R/O Village & P.O. Hikkam, Tehsil Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Smt. Chhering Butit W/O Shri Chhering Chhutup daily wage worker by the Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. October, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.***LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, the 4th June, 2011*

**No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Chhering Dolma W/O Shri Dorje Chhering R/O Village Langcha, P.O. Hikkam, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Smt. Chhering Dolma W/O Shri Dorje Chhering daily wage worker by the Executive Engineer, H. P. P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. September/October, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 8th June, 2011*

**No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Chhering Dolma W/O Shri Sonam Tashi R/O Village & P.O. Kaza, Tehsil Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Smt. Chhering Dolma W/O Shri Sonam Tashi daily wage worker by the Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. 01-11-2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, 4th June, 2011*

**No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Chhewang Lamo W/O Shri Nawang Zinpa R/O Village & P.O. Kaza, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Smt. Chhewang Lamo W/O Shri Nawang Zinpa daily wage worker by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. September/October, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.***LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, 29th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Jaswant Kumar S/O Shri Karam Chand R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power

vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Jaswant Kumar S/O Shri Karam Chand Batching Plant Operator by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Batching Plant Operator is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 30th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Jeet Ram S/O Shri Achhar Singh R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Jeet Ram S/O Shri Achhar Singh Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel

T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?"

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 3rd June, 2011*

**No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Labu Chhering S/O Shri Angroop Thuktan R/O Village Langcha, P.O. Hikkam, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Shri Labu Chhering S/O Shri Angroop Thuktan daily wages workman by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. September, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to him have been retained by the employer, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 27th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Madan Lal S/O Shri Roshan Lal R/O Village

Bharer, P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Madan Lal S/O Shri Roshan Lal Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 13th June, 2011*

**No. 11-1/86(Lab) I.D/2011-Nahan.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Mahima Chand S/O Shri Tota Ram R/O Village Ghaina, P.O. Rama, Tehsil Nahan, District Sirmour, H.P. Vs. The Collector Forest Settlement Solan and Sirmour at Nahan, District Sirmour, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Shri Mahima Chand S/O Shri Tota Ram chainman by the Collector Forest Settlement Solan and Sirmour at Nahan, District Sirmour, H.P. w.e.f. Year, 2007 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to him have been retained by the employer, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?”

Sd/-  
*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 4th June, 2011*

**No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Nawang Namgial S/O Shri Panma Namgial R/O Village Langcha, P.O. Hikkam, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Shri Nawang Namgial S/O Shri Panma Namgial daily wages workman by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. October, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to him have been retained by the employer, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?”

Sd/-  
*Labour Commissioner.*

**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, July, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Om Parkash S/O Shri Hirda Ram R/O Village and P.O. Deol, Tehsil Baijanth, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Om Parkash S/O Shri Hirda Ram Grade Unskilled by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Grade Unskilled is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.***LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, 8th June, 2011*

**No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Padma Dolkar W/O Shri Nawang Lotey R/O Village & P.O. Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.



Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Smt. Padma Dolkar W/O Shri Nawang Lotey daily wage worker by the Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. 01-11-2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 30th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Pappu Ram S/O Shri Prem Chand R/O Village and P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Pappu Ram S/O Shri Prem Chand Pump Operator by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Pump Operator is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, 29th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Partap Chand S/O Shri Dumnu Ram R/O Village and P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Partap Chand S/O Shri Dumnu Ram Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.***LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, 29th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Pyar Chand S/O Shri Prem Chand R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Pyar Chand S/O Shri Prem Chand Filed Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?”

Sd/-  
Labour Commissioner.

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 27th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Raj Kumar S/O Shri Nikku Ram R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Raj Kumar S/O Shri Nikku Ram Batching Plant Operator by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/SSubhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?”

Sd/-  
Labour Commissioner.

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 27th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Rakesh Kumar S/O Shri Chokas Ram R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Rakesh Kumar S/O Shri Chokas Ram Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?”

Sd/-  
Labour Commissioner.

**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, July, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Sanjay Kumar S/O Shri Krishan Chand R/O Village Dhandhera, P.O. Kachhera, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Sanjay Kumar S/O Shri Krishan Chand Senior Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Senior Field Attendant is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.***LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, 27th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Sanjeev Kumar S/O Shri Punjaba Ram R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Sanjeev Kumar S/O Shri Punjaba Ram Senior Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1stFloor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 2th June, 2011*

**No. 11-1/86(Lab) I.D/2011-Nahan.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Santosh Kumar S/O Shri Gaddi Lal R/O Village Paffari, District Hamirpur, H.P. Vs. The Managing Director, M/S Shivalik Containers Private Limited, Unit-II, Plot No.-7, Industrial Area, Phase-II, Kala-Amb, District Sirmour, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Shri Santosh Kumar S/O Shri Gaddi Lal operator by the management of M/s Shivalik Containers Private Limited, Unit-II, Plot No.-7, Industrial Area, Phase-II, Kala-Amb, District Sirmour, H.P. w.e.f. July, 2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the worker is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, 21st June, 2011*

**No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Sonam Butith D/O Shri Angrup Thuktan R/O Village Langcha, P.O. Hikkam, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Smt. Sonam Butith D/O Shri Angrup Thuktan daily wage worker by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. October, 2008 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

---

**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, 8th June, 2011*

**No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Sonam Chhodon W/O Shri Tanpa Chhering R/O Village Sichling, P.O. Dhankar, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Smt. Sonam Chhodon W/O Shri Tanpa Chhering daily wage worker by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. September, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?”

Sd/-  
*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, July, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Subhash Chand S/O Shri Ajit Singh R/O Village and P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Subhash Chand S/O Shri Ajit Singh Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?”

Sd/-  
*Labour Commissioner.*



**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, 27th June, 2011*

**No. 11-6/85(Lab) I.D/2011-Shimla.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Tek Singh S/O Shri Lachhmi Dass R/O Village Panehra, P.O. Chaba, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.S.E.B. Electrical Division, Sunni, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the verbal termination of services of Shri Tek Singh S/O Shri Lachhmi Dass daily wage beldar by the Executive Engineer, H.P.S.E.B. Electrical Division, Sunni, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P. w.e.f. 21-03-1998 (Dispute referred keeping in view the order dated 09-01-2006 of Himachal Pradesh State Administrative Tribunal Shimla in O.A. 1808/1999 filed by the above named worker) without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to him have been retained by the employer, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, to what wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.***LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, 29th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Trilok Chand S/o Shri Saraf Ram R/O Village Jamurapur, P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but

could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Trilok Chand S/O Shri Saraf Ram Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 29th June, 2011*

**No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Uttam Chand S/O Shri Shakti Chand R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.

As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of the services of Shri Uttam Chand S/O Shri Shakti Chand Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Bangalore, 560038 (2) The General

Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?"

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 8th August, 2011*

**No. 11-5/99(Lab) ID/2009/Chamba.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Arun Kumar S/O Sh. Dev Brat Sharma Jagdish R/O Village- Bhatoli, P.O. Bathri, Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba, H.P. V/s The Executive Engineer, IPH Division Dalhousie, Distt. Chamba,(H.P.).

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether termination of the services of Sh. Arun Kumar S/O Sh. Dev Brat Sharma, R/O Village- Bhatoli, P.O. Bathri, Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba, H.P. by the Executive Engineer, IPH Division Dalhousie, Distt. Chamba, (H.P.) w.e.f. 01.10.1998 is proper and justified, if not, what amount of back wages, seniority, pastservice benefits and compensation the above workman is entitled to from the above employer?”

Sd/-

*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 17th August, 2011*

**No. 11-23/84(Lab) ID/09/Mandi.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Bablu Ram S/O Sh. Mast Ram, Village- Hiyun Jandwl, PO-Hiyun, Tehsil-Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether retrenchment of services of Sh. Sh. Bablu Ram S/O Sh. Mast Ram, Village-Hiyun Jandwl, PO-Hiyun, Tehsil-Sarkaghat, Distt. Mandi by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi w.e.f. 08.7.2005 as mason, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?”

Sd/-  
*Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, 18th August, 2011*

**No. 11-23/84(Lab) ID/11/Mandi.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Smt. Brahmi Devi W/O Sh. Bidhi Chand, Village-Sanhali, P.O. Tulah, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. V/S The Divisional Forest Officer, Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:-

“Whether termination of the services of Smt. Brahmi Devi W/O Sh. Bidhi Chand, Village-Sanhali, P.O. Tulah, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. by The Divisional Forest Officer, Joginder Nagar, Distt. Mandi w.e.f. August, 2009 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer ?”

Sd/-  
*Labour Commissioner.*

**FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT****NOTIFICATION**Shimla-2, 17<sup>th</sup> January, 2012

**No. FDS-F(10)8/2006.**—In partial modification of this Department notification of even number dated 11.12.2008 and 22.7.2009, regarding the constitution of Flying Squad, the same is modified to the extent of following substitutions with immediate effect:-

In North Zone, comprising District Kangra, Chamba (except Pangi Sub-division) Una and Hamirpur.

1. Food and Supplies Officer, O/O District Controller (FCS&CA) Kangra at Dharamshala in place of Food & Supply Officer, Zonal Office, Dharamshala.
2. Inspector, Food and Supplies, Dehra in place of Inspector (F&S) Pragpur.

By order,

Sd/-

Pr. Secretary (FCS&amp;CA).

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 16 जनवरी, 2012

**संख्या डब्ल्यू एल एफ-ए(3) 7/96-II.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: डब्ल्यू एल एफ-ए(3) 7/96 तारीख 4.6.2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.**—(1) हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध-"क" में (1) स्तम्भ संख्या-10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) नब्बे प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) दस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।"

(2) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान मुख्य उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

- “(i) पच्चीस प्रतिशत सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
- (ii) बीस प्रतिशत तहसील कल्याण अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवा काल हो।
- (iii) बीस प्रतिशत सांख्यिकी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवा काल हो।
- (iv) पच्चीस प्रतिशत वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम बारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके बारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

पदों को भरने के लिए निम्नलिखित रोस्टर लागू होगा :—

पहला, चौथा, सातवां ग्यारहवां सत्रहवां  
पांचवां, नववां, बारहवां, उन्नीसवां  
तीसरा, छठवां, दसवां, पंद्रहवां  
दूसरा, आठवां, तेरहवां, सोलहवां, अठारहवां  
चौदहवां, एवं बीसवां

सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी  
तहसील कल्याण अधिकारी  
सांख्यिकी सहायक  
वरिष्ठ सहायक  
सीधी भर्ती द्वारा ।”

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)।

*[Authoritative English Text of this department notification No. WLF-A(3)-7/96-II dated 16-01-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 16 th January, 2012*

**No. WLF-A(3)-7/96-Vol.-II.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment, Child Development Project Officer Class-II Gazetted Recruitment and Promotion Rules 2007 notified vide this Department notification No. WLF-A (3)-7/96 dated 4-6-2007, namely :—

**1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Child Development Project Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion ( 1st Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure-A.**—(1) In Annexure-A to the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department Child Development Project Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 200, for the existing provisions against Col.No.10 the following shall be substituted, namely:-

“ (i) 90% by promotion failing which by Direct Recruitment.

(ii) 10% by direct Recruitment or on contract basis.”;

(2) For the existing main provisions of Column No. 11 the following shall be substituted namely :-

“ (i) 25% by promotion from amongst Assistant Child Development Project Officer having at least 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(ii) 20% by promotion from amongst the Tehsil Welfare Officers having at least 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(iii) 20% by promotion from amongst the Statistical Assistants having at least 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(iv) 25% by promotion from amongst the Senior Assistants having at least 12 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered, if any, in the grade.

The following roster shall be applied for filling up the posts:-

1st , 4th , 7th , 11th , 17<sup>th</sup>  
5th , 9th , 12th , 19<sup>th</sup>  
3rd , 6th , 10th , 15<sup>th</sup>  
2nd , 8th , 13th , 16th , 18<sup>th</sup>  
14th & 20th

ACDPO  
Tehsil Welfare Officer  
Statistical Assistant  
Senior Assistant  
Direct recruitment.”

By order,  
Sd/-  
Pr. Secretary(SJ&E).

